(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है, जिसमें राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा खेतिहार मजदूरों एवं भूमिहीन किसानों की सहकारी समितियों को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। [**पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या** LT—59/68]

COOPERATIVE SOCIETIES

445. SHRI BHOGENDRA JHA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the total number of service, multipurpose, labour and other types of coperatives in the country, State-wise, with their total membership and share capital; and

(b) whether Government propose to give credit to the rural areas only through the Cooperative Societies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): (a) A statement showing the position by the end of June 1965, the latest year for which statistical data have been compiled and published is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-60/68].

(b) No, Sir.

खेती योग्य परती भूमि

446. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों की मलकियत में खेती योग्य, परती भूमि कितनी कितनी है ;

(ख) भूतपूर्व भारतीय रियासतों के भूतपूर्व नरेशों की मलकियत में ऐसी कितनी परती भूमि है ;

(ग) ऐसी परती भूमि में खेती कराने के लिये सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इसको शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वित करवाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) देश में सरकारी तथा ग़ैर सरकारी व्यक्तियों की मलकियत में खेती योग्य परती भूमि संबंधी विवरण सभा पटल पर रखा है । [**पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या** LT—61/68]

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ). परती भूमि और खेती योग्य बंजर भूमि में कृषि करने के लिए विभिन्न राज्य प्लान योजनाओं, केन्द्र द्वारा परिचालित बंजर भूमि सुधार योजना को भूमि हीन कृषि मजदूरों के पुनर्स्थापन के लिए बंजर भूमियों के सुधार की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत और कृषि वित्तीय निगम की सहायता के साथ सहकारी भूमि विकास बैंकों के द्वारा चलाया गया क्षेत्र विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में भूमि सुधार किया जा रहा है। प्राय: सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेश में (दिल्ली, चण्डीगढ़ और लक्का द्वीप और अमिनदिवि द्वीप समूह के अतिरिक्त) भूमि सुधार योजनायें हैं। सन् 1967—68 के लिए 3.6 लाख एकड़ का भौतिक लक्ष्य है और 1968—69 के लिए 4.1 लाख एकड़ का परिशोधित भौतिक लक्ष्य का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त, प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्र में लगभग 15 लाख एकड़

के सुधार और विकास की योजनायें कृषि वित्त निगम की सहायता से अनुमानतः 33 करोड़ रुपये से चलायी गयी है। ये योजनायें अपने ढंग और अपने विस्तार के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

खेती योग्य परती भूमि में खेती करने के प्रश्न पर सरकार निरन्तर विचार कर रही है। फिर भी, समस्त खेती योग्य परती भूमि में आर्थिक दृष्टि से खेती नहीं की जा सकती है और इस कार्य के लिए अनुपातत: भारी वित्तीय विनियोग की आवश्यकता होती है जो सबसे बड़ी एक बाधा है।

उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा उर्वरकों का वितरण

447. **श्री मोहन प्रसाद :**
श्री राम चरण :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1967 से नवम्बर, 1967 तक उत्तर प्रदेश में सहकारी संस्थाओं द्वारा नंगल के कैल्शियम उर्वरकों और सिन्दरी के उर्वरकों को बड़े पैमाने पर चोर बाजारी में बेचा गया और उसके फलस्वरूप किसानों को उर्वरक नहीं मिल सके ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उर्वरकों को बेचने के लाइसेंस और कोटे उत्तर प्रदेश में कुछ व्यक्तियों को ही दिये गये थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार को कुछ ऐसे मामलों की सूचना मिली है, जिनमें कुछ लोगों के लाइसेंस जारी करने के तत्काल बाद रद्द कर दिये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (घ). पूछी गई जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

PROCUREMENT OF FOODGRAINS

448. SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH:
SHRI SRADHAKAR SUPAKAR:
SHRI RABI RAY:
SHRI MOHSIN:
SHRIMATI JYOTSNA CHANDA:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the target fixed for the procurement of foodgrains for 1967-68;

(b) the actual achievement in this regard, and the reasons for the shortfall, if any;

(c) whether any procurement plan has been worked out for the next year;

(d) if so, the main features thereof; and

(e) the total quantity of foodgrains likely to be procured in the next year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) The all-India target for procurement of foodgrains during 1967-68 recommended by the Agricultural Prices Commission is 8 million tonnes; 7 million tonnes for kharif grains and 1 million tonnes for rabi grains.

(b) A statement showing the quantities of kharif grains actully procured so far according to the latest reports available is laid on the Table of